



नारायणी बहुभाषी संग्रहालय ने लगाई प्रदर्शनी

रायपुर। हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर प्रेस क्लब रायपुर द्वारा राम मंदिर स्थित सुंदर भवन और छत्तीसगढ़ मित्र एवं कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में बैरन बाजार स्थित आशोबांद भवन में शनिवार को विभिन्न आयोजन किया गया। इन दोनों ही आयोजनों में नारायणी बहुभाषी संग्रहालय ने 30 से अधिक भाषाओं के समाचार पत्रों, 20 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित रामायण की प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ी, संस्कृत, हरियाणवी, गढ़वाळी, ख़ासी, उर्दू, कोंकणी, कन्नड़, पंजाबी, बोडो, ओड़िया, मराठी, मलयालम, गुजराती, सिंधी, असमिया, डोगरी, किरातराई, भूटिया, लिम्बु, तिब्बतन भोटी, मंगर, तमांग, सुनुवार (मुखिया), गुरुंग, लेप्चा, शरपा, नेपाली सहित अमेरिका, नीदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के समाचार पत्र भी प्रदर्शित किए गए थे।

पुराने लेन-देन को लेकर युवक से मारपीट

रायपुर। रायपुरा क्षेत्र में पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में युवक को चोट आई है, जिसके बाद उसने अस्पताल में उपचार कराकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, विकास विहार कॉलोनी रायपुर निवासी एक युवक बैटरी डिजाइन इंजीनियर के रूप में कार्यरत है और बी-टेक की पढ़ाई कर चुका है। वह 29 मई की रात अपने दोस्तों राहुल श्रीवास, कुनाल साहू और पीयूष के साथ स्कूटी से रायपुरा बस्ती होते हुए सरोना जा रहा था। जब वह निषादपारा रायपुरा स्थित गोठान के पास पहुंचा, तब वहां खड़े राजा निषाद और छाटू पाल ने उसे आवाज देकर रोका और पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू कर दिया।

राजधानी की चारों दिशाओं में तालाब संरक्षण महामियान

रायपुर। ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर शहर के विभिन्न तालाबों के संरक्षण, पुनर्जीवन एवं स्वच्छता हेतु व्यापक जनअभियान चलाया जा रहा है। संस्था द्वारा तालाबों के संरक्षण, गहरीकरण, जल शुद्धिकरण व्यवस्था तथा तालाबों में मिल रहे गंदे तालों पर रोक लगाने सहित विभिन्न जनहितकारी मांगों को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि ग्रीन आर्मी द्वारा वर्तमान में हांडी तालाब ताल्यापारा, बंधवा तालाब लाखेनगर, गोपिया डबरी प्रोफेसर कॉलोनी मार्ग, महाराजबंध तालाब पुरानी बस्ती, बदलावा तालाब लाखेनगर, आमा तालाब-1 एवं आमा तालाब-2 देवपुरी, राजा तालाब, कल्याण सागर गढ़ही तालाब रायपुरा, आत्मानंद तालाब चौबे समता कॉलोनी तथा भुईया तालाब टाटीबंध, शीतला तालाब सहित रायपुर के 11 प्रमुख तालाबों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक अमिताभ दुबे, रायपुर जिला अध्यक्ष गुरदीप टुटेजा, भारती श्रीवास्तव ब्लू विंग अध्यक्ष, मोनिका बागरेचा ग्रीन विंग अध्यक्ष, संजय भूमिक ब्राउन विंग अध्यक्ष, श्याम बघेल व्हाइट विंग अध्यक्ष समेत पदाधिकारी, सदस्य महाभियान में जुटे हुए हैं।

निगम का विद्युत विभाग फिसड़ी, शिकायत के बाद भी सुधर नहीं रही व्यवस्था

अंधेरे में सिस्टम, स्ट्रीट लाइट की थोक में शिकायतें, पर समाधान नहीं, निगम लाचार

रहवासी नाराज मुशासन तिहार में कर रहे स्ट्रीट लाइट बंद की शिकायतें

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

नगर निगम का विद्युत विभाग शहर सहित आउटर इलाकों में स्थित वार्डों में आमजनों को स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देने के मामले में फिसड़ी साबित हो रहा है। हालत ये है कि स्ट्रीट पोल में लगी पुरानी लाइट की मरम्मत समय पर नहीं हो रही है, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को बदला नहीं जा रहा है। पार्षदों द्वारा स्ट्रीट लाइट की मांग करने पर उनकी अनदेखी की जा रही है। विभाग के संबंधित अधिकारी के टालमटोल पूर्ण रवैये से भी लोग बेहद परेशान हैं। महापौर और निगम आयुक्त से शिकायत के बाद अब सुशासन तिहार में भी स्ट्रीट लाइट की समस्या की शिकायत लोग खुलकर कर रहे हैं।

केस 1

वीर शिवाजी वार्ड में 60 लाइटें बंद, 20 दिन से शिकायत

नगर निगम जोन 1 के वीर शिवाजी वार्ड के साहूपारा, शिवानंद नगर खमतराई, नीम डबरी तालाब इलाका, बम्हदेईपारा, संन्यासी पारा, शहीद नगर, खमतराई बाजार मुख्य मार्ग, संतोषी नगर में 20 दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। वार्ड पार्षद और जोन अध्यक्ष गजजू साहू ने जोन में इसकी शिकायत की तो जवाब मिला, लाइट उपलब्ध नहीं है। इससे लोगों को अंधेरे में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि वार्ड में 60 स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जिन्हें रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए अब वे सीधे निगम आयुक्त को इसकी शिकायत करेंगे।

केस 2

यहां स्ट्रीट लाइट खराब, बदल नहीं रहे

बाबू जगजीवनराम वार्ड की डूंडा बस्ती, देवपुरी और डुमरतराई इलाके में स्ट्रीट लाइटें खराब होने से लोग परेशान हैं। पुरानी लाइट की रिपेयरिंग नहीं हो रही और नई लाइट उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इससे रहवासी इलाके में अंधेरा होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्ड पार्षद मनोज जांगड़ ने बताया कि जोन 10 कमिश्नरी में इसकी शिकायत की है, इसके बाद भी स्ट्रीट लाइट्स बदली नहीं जा रही है। जोन में हुई समीक्षा बैठक में भी हमने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने की मांग की थी। निगम मुख्यालय में बैठे विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी स्ट्रीट लाइट की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे लोगों में आक्रोश की स्थिति है। सुशासन तिहार में इस बार स्ट्रीट लाइट की शिकायत बड़ी संख्या में लोग करने वाले हैं।

केस 4

संत रविदास वार्ड

नगर निगम जोन 8 के संत रविदास वार्ड स्थित रायपुरा के बघवा तालाब गार्डन के दोनों तरफ तालाब सौंदर्यीकरण के दौरान लाखों खर्च कर लगाई गई स्ट्रीट लाइटें कभी कभार ही जलती हैं। इसके चलते शाम ढलते ही इस क्षेत्र में अंधेरा होने से रायपुरा, विप्रनगर सहित आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। इसी तरह विप्रनगर की स्ट्रीट पोल शो पीएस बने हुए हैं। जोन 8 कमिश्नरी में शिकायत के बाद भी बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को चालू नहीं कराया जा रहा है। बगौये के एक तरफ की लाइट बंद रहने से लोग शाम के समय वाहकर भी यहां नहीं आ रहे। अंधेरा होने से असमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर निगम के संबंधित इंजीनियर का कहना है कि सिंगल फेज होने से लोड की समस्या है, इसलिए थ्री फेज कनेक्शन के साथ नया मीटर लगवाने नगर निगम ने सीएसईबी में राशि जमा करा दी है। जल्द ही बघवा तालाब और विप्रनगर में स्ट्रीट लाइट की सुविधा लोगों को मिलने लगेगी।



केस 3

कानरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

नई कॉलोनियों में 3 साल से नए पोल, लाइट ही नहीं

नगर निगम के जोन-10 स्थित कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड के अक्षत विहार, सिद्धि विनायक कॉलोनी, ग्रीन सिटी, दुर्गा विहार कॉलोनी में प्रकाश व्यवस्था के लिए 3 साल पहले नगर निगम की ओर से नए स्ट्रीट पोल लगवाए गए, पर आज तक इन स्ट्रीट पोल्स पर लाइट नहीं लगाई जा सकी है। इससे लोगों को स्ट्रीट लाइट की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि लोगों ने मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराते समय विकास शुल्क की राशि जमा करा दी थी। वार्ड पार्षद सुषमा-तिलक साहू ने बताया कि नई कॉलोनियों में 550 स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। बिना स्ट्रीट लाइट के विद्युत पोल महज शोपीस बनकर रह गए हैं।

केस 5

जवाहर लाल नेहरू वार्ड

लाइटें बंद, सुनते नहीं अधिकारी

हाल ही में शहर में तेज आंधी तूफान के दौरान वार्ड के कई इलाकों की स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं, इसे सुधारने निगम मुख्यालय के विद्युत विभाग के अधिकारी से आग्रह किया, पर उन्होंने अब तक केवल आश्वासन ही दिया है, वार्ड में झांकने तक नहीं आए। ये कहना है पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड के पार्षद भगतराज हरवंश का। उन्होंने बताया कि जय भीम नगर, एकता नगर, कबीर नगर, एकता कालोनी की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। कम से कम 260 स्ट्रीट लाइटों की जरूरत है। जनता की परेशानी को देखते हुए पार्षद निधि से 1.50 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइटें खरीदने प्रस्ताव बनवा रहे हैं।

किसानों की बड़ी चिंता

मांग अधिक होने से महामाया की आपूर्ति में लेटलतीफी



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ के किसानों को महामाया धान बीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समितियों और बीज केंद्रों में मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं होने से किसानों में चिंता बढ़ गई है। समय पर बीज नहीं मिलने से धान की बोनी और रोपाई प्रभावित होने की आशंका है।

किसानों ने कृषि विभाग से महामाया बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। बताया जाता है कि राजनांदगांव, धमतरी, कबीरधाम और अन्य धान उत्पादक जिलों में किसानों द्वारा महामाया धान बीज की उपलब्धता को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि रायपुर और दुर्ग जिले में कृषि विभाग ने पर्याप्त बीज उपलब्ध होने का दावा किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि लोकप्रिय किस्मों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है।

प्रदेश में 4.87 लाख विंटल बीज का भंडारण

खरीफ 2026 के लिए किसानों की मांग के अनुरूप लगभग 4.95 लाख विंटल प्रमाणित बीज की मांग दर्ज की गई थी, जिसके विरुद्ध लगभग 4.87 लाख विंटल बीज का भंडारण किया गया। इसमें में धान के बीज के लिए 168626 विंटल का भंडारण किया गया है। इनमें से 18752 विंटल बीज वितरित किए जा चुके हैं। समितियों में 149531 विंटल शेप है।

मध्यम अवधि वाली किस्मों की मांग

स्थिति क्षेत्रों में मध्यम अवधि वाली किस्में तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल्दी पकने वाली किस्मों का वितरण किया जाता है। समितियों के प्रबंधकों का कहना है कि हाल के वर्षों में किसानों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली किस्मों में महामाया, राजेश्वरी और एलटीयू-1010 शामिल हैं। इसके चलते कुछ समितियों में इनकी अस्थायी कमी की शिकायतें भी सामने आती हैं। राज्य सरकार और बीज निगम हर खरीफ सीजन में लाखों विंटल प्रमाणित बीज सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।

कांजी हाउस में गोमाता को 33 प्रकार के फलों का भोग किया अर्पित



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

पवित्र पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि के अवसर पर सामाजिक संस्था जंदगी ना मिलेगी दोबारा परिवार द्वारा लाखेनगर स्थित कांजी हाउस में गोसेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने गोमाताओं को 33 प्रकार के फलों का भोग अर्पित किया। संस्था विगत 4 वर्षों से निरंतर चोकर, कुट्टी, तिबारा, फल्ली एवं हरी सब्जियां खिलाकर गोसेवा का कार्य कर रही है। संस्था द्वारा घुमंतू गोमाताओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम पट्टी लगाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे रात्रि के

समय वाहन चालकों को गोवंश दूर से ही दिखाई दे सके। संस्था की संस्थापक सुषमा तिवारी ने बताया कि 33 कांति देवी-देवताओं से प्रार्थना करते हुए संस्था समाज को यह संदेश देना चाहती है कि गोमाताओं की रक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। साथ ही संस्था ने शासन-प्रशासन से निवेदन किया है कि गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए एवं उनकी निर्मम हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। कार्यक्रम में ममता बड़गैय्या, स्वाति सोनी, सीमा विजय शर्मा, वर्षा दुबे, लता साहू, विनीता शर्मा, राधिका सोनकर, संध्या दुबे, सरिता विश्वकर्मा, अविनाश दुबे आदि उपस्थित रहे।

समान काम, समान वेतन पर दिया जोर

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने मजदूरी संहिता 2026 के प्रारूप को लेकर श्रम विभाग को सुझाव भेजे हैं। फेडरेशन ने कहा है कि शासकीय कार्यालयों में काम कर रहे अनियमित कर्मचारियों के हित में नियमों में बदलाव किए

न्यूनतम मूल वेतन 30 हजार रुपए करने की मांग

फेडरेशन ने मजदूरी संहिता प्रारूप को लेकर श्रम विभाग को भेजे सुझाव

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

जाने चाहिए। फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने शासन को बिंदुवार सुझाव दिए हैं। इनमें प्रमुख रूप से समान काम, समान वेतन पर जोर दिया गया है, इसके साथ ही न्यूनतम मूल वेतन 30 हजार रुपए करने की मांग की गई है। साथ ही आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय 10 फीसदी



प्रस्तावित किया गया है, उसे 30 फीसदी करने, बच्चों की शिक्षा व्यय,

चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 फीसदी होगा, इसमें संचार सुविधा, जैसे मोबाइल को भी जोड़ने और 25 फीसदी में वृद्धि कर 35 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मपदंड उपनियम में शासकीय

क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को जोड़ने, प्रावधानित तकनीकी समिति में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग को सुझाव प्रेषित किया है। फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष युगल किशोर साहू ने कहा, न्यूनतम मूल वेतन 2017 में पुनरीक्षित किया गया था।

सरकारी अस्पतालों तक सीमित पीएम राहत योजना

30 से ज्यादा घायलों को मुफ्त इलाज

अस्पतालों में मरीजों का इलाज कराने कवायद जारी अब तक 5 केस में भुगतान

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

सड़क हादसे में घायल होने वालों में सात दिनों तक डेढ़ लाख कैशलेस इलाज की सुविधा अभी सरकारी अस्पतालों तक सीमित है। रायपुर जिले में अब तक 30 से ज्यादा घायलों को इस कैशलेस स्कीम का लाभ मिला है। रायपुर जिला योजना में इलाज कराने और संबंधित अस्पतालों को भुगतान कराने में प्रदेश में अखल है। निजी अस्पतालों में इस योजना को लागू करने करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क हादसे का शिकार होने वाले मरीजों को किसी भी अस्पताल में सात दिनों तक डेढ़ लाख तक के निशुल्क इलाज की योजना लागू की गई है। इस योजना का क्रियाव्यवण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और रायपुर जिला इस मामले में अखल है। जिले के शासकीय डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे 30 से ज्यादा मरीजों को योजना के तहत निशुल्क सुविधा का लाभ मिला है, यानी ऐसे मरीज आयुष्मान योजना के हितग्राही नहीं होने के बाद भी कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

भुगतान पर अटक रहा मामला

सूत्रों के अनुसार योजना में निजी अस्पतालों के शामिल होने का मामला भुगतान प्रक्रिया पर अटक रहा है। इस योजना में उन्हीं अस्पताल को पंजीकृत माना गया है, जो आयुष्मान की इंपैक्ट लिस्ट में शामिल हैं। आयुष्मान योजना में भुगतान राशि के मामले में कटू अनुभव से गुजरने वाले हॉस्पिटल इसकी शीघ्र प्रक्रिया के लिए आश्चर्य होना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी निजी हॉस्पिटलों को इस योजना से जोड़ने की कवायद में जुटा हुआ है।

आर्थिक बोझ कम करना उद्देश्य

सूत्रों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य एक्सीडेंट का शिकार होने वाले मरीज और उसे परिवार का आर्थिक बोझ कम करना है। इसके अलावा एक्सीडेंट के आंकड़ों के आधार पर समीक्षा के बाद इसके रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किया जाना है। इस योजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल पर लागू किया गया है। साथ ही इसमें स्वास्थ्य, पुलिस, नगरपाल प्रशासन, परिवहन विभाग को भी शामिल किया गया है।

मिल रहा लाभ

योजना के अंतर्गत एक्सीडेंट में घायल होने वालों को लाभ मिल रहा है। रायपुर जिले में एक 83 साल के बुजुर्ग का इस योजना के तहत इलाज कराया गया है। योजना के तहत इलाज के भुगतान की प्रक्रिया तेजी से कराने के मागलो ने रायपुर छत्तीसगढ़ में अवल है।

डॉ. सार्थक नंदा, जिला नोडल, पीएम राहत योजना

खबर संक्षेप



हिंदी पत्रकारिता की दो शताब्दियों की गौरवपूर्ण यात्रा और वर्तमान स्वरूप पर चर्चा

रायपुर। कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में हिंदुस्तान के प्रथम हिंदी समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ के प्रकाशन के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने ‘उदन्त मार्तण्ड’ के 200 वर्ष पूर्ण होने को हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का एक गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायी अवसर बताते हुए पत्रकारिता के मूल्यों, निष्पक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता की दो शताब्दियों की गौरवपूर्ण यात्रा, उसके संघर्ष, विकास और वर्तमान स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर डॉ. सुशील त्रिवेदी ने हिंदी पत्रकारिता की परंपरा एवं उसके सामाजिक दायित्वों पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डॉ. श्रीराम परिहार ने ‘उदन्त मार्तण्ड’ से लेकर वर्तमान डिजिटल पत्रकारिता तक की 200 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का विस्तृत एवं तथ्यपरक विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विभिन्न कालखंडों में हिंदी पत्रकारिता ने समाज जागरण, राष्ट्रीय चेतना तथा जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सुरेश मिश्रा, प्रख्यात साहित्यकार एवं चिंतक डॉ. श्रीराम परिहार, डॉ. सुशील त्रिवेदी, वीरेंद्र पाण्डेय, डॉ. प्रभात मिश्रा, डॉ. शशांक शर्मा, डॉ. रविन्द्र मिश्रा, डॉ. श्रीचंद मिश्रा, डॉ. सुधीर शर्मा, बड़ी संख्या में साहित्य, पत्रकारिता एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े नागरिक उपस्थित रहे।

डाइट में विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर व्याख्यान का आयोजन

हरिभूमि न्यूज ►► महासमुंद

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में प्राचार्य अरुण कुमार प्रधान, उपप्राचार्य उमादेवी शर्मा के निर्देशन एवं साहित्यिक प्रभारी एवं कार्यक्रम समन्वयक व्याख्याता टेकराम सेन के संयोजन में अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर व्याख्याता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राध्यापकों को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रधान ने कहा कि हम सभी राष्ट्र निर्माता है इसलिए हमें

बिजली नियामक आयोग में चल रहा मंथन

लगेगा महंगी बिजली का झटका, इस माह नया टैरिफ जारी करने की तैयारी



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को इस माह जून से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। नए सत्र के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी करने की बिजली नियामक आयोग में तैयारी चल रही है। जून में कभी भी इसकी जारी किया जा सकता है। आयोग तय करेगा कि नया टैरिफ जून से लागू होया या फिर अगले माह जुलाई से। टैरिफ पर फैसला करने में इसलिए विलंब हो रहा है, क्योंकि आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनियों ने अपने आगे वाले चार साल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। इसका आकलन करने में ज्यादा समय लग रहा है। इसी के साथ नए सत्र के लिए 63 सौ करोड़ घाटे की याचिका को कारण भी इसके मंथन में विलंब हो रहा है। नियमों के मुताबिक जब पॉवर कंपनी नए सत्र के लिए टैरिफ का लेखा-जोखा नियामक आयोग में देती है तो उसको चार साल के खर्च का हिसाब देना रहता है। एक बार चार साल का लेखा-जोखा देने के बाद फिर हर साल चार साल का लेखा-जोखा देने की जरूरत नहीं होती है। इसके समाप्त होने पर ही फिर से चार साल का लेखा-जोखा देना पड़ता है।

63 सौ करोड़ घाटे की याचिका

पॉवरकंपनी ने नए सत्र 2026-27 के लिए पूरा लेखा-जोखा बनावट नियामक आयोग में नए टैरिफ के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका में बताया गया है कि प्रचलित दर से 26216 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है। इसी के साथ साल भर का खर्च 25460 करोड़ बताया गया है। ऐसे में 756 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन इसी के साथ पिछले सत्रों की राशि का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि नए सत्र के फायदे को पुराने अंतर की राशि में कम करने के बाद भी 63 सौ करोड़ के राजस्व की और जरूरत होगी। नए सत्र में 26 सौ करोड़ का राजस्व मिलेगा। पुराना घाटा 63 सौ करोड़ है, ऐसे में नए सत्र के लिए कुल 32 हजार पांच सौ करोड़ से ज्यादा के राजस्व की जरूरत बताई गई है।

हरिभूमि न्यूज ►► बसना

शनिवार शाम आई तेज आंधी, तूफान और बारिश के बाद ग्राम सिरको सहित आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। प्राकृतिक आपदा के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीणों को भीषण गर्मी और नवतपा के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवा के कारण अनेक स्थानों पर पेड़-पौधे उखड़

गए, बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त हो गए तथा कई मकानों की सीट और छप्पर भी उड़ गए,बिजली के खंभे तक टूटे पड़े मुख्य मार्गों पर पेड़ गिरने से घंटों तक यातायात बाधित रहा। आपदा के बाद राहत एवं मरम्मत कार्यों में अपेक्षित शासकीय सहायता नहीं मिलने से ग्रामीण स्वयं श्रमदान कर रास्ते साफ करने और अन्य समस्याओं के समाधान में जुटे रहे। बिजली आपूर्ति ठग होने से गांव में पेयजल संकट भी गहरा गया है। नवतपा की भीषण गर्मी में लोगों को नहाने, खाने-पीने तथा शौचालय उपयोग जैसी दैनिक आवश्यकताओं के



लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों में ग्रामीणों ने निजी जनरेटर की व्यवस्था कर नलकूपों से पानी निकालकर किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी कीं।

ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फॉल्ट की तलाश की जा रही है तथा बिजली बहाली में अभी दो दिन और लग सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि समाचार लिखे जाने तक सिरको गांव में विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। वहीं

जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 98 लाख रुपए की लागत से योजना स्वीकृत होने के बावजूद अब तक कई स्थानों पर पाइपलाइन तक नहीं बिछाई जा सकी है। परिणामस्वरूप बिजली संकट के दौरान ग्रामीणों को पानी के लिए भी भारी मशकत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल करने, क्षतिग्रस्त विद्युत ढांचे की मरम्मत कराने तथा पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

मनमानी : पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास कार्य लंबित

कार्यालयीन समय में सचिव की अनुपस्थिति, भटक रहे ग्रामीण

हरिभूमि न्यूज ►► बसना

ग्राम पंचायत सिरको में कार्यालयीन

- मामला सिरको पंचायत का, विकास कार्यों की लक्ष्य और पूर्णता पर उठे सवाल

समय के दौरान पंचायत सचिव के अनुपस्थित पाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मीडियाकर्मियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पंचायत कार्यालय में सचिव मौजूद नहीं मिले।

मीडियाकर्मियों ने पंचायत सचिव अरुण बुड़ेक से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने निवास में होने की जानकारी दी। कार्यालयीन समय में सचिव की अनुपस्थिति को लेकर



ग्रामीणों ने पंचायत कार्यों के संचालन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास कार्य लंबित पड़े हुए हैं, वहीं आवश्यक दस्तावेजी कार्यों एवं प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों के लिए लोगों को बार-

विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन संभव नहीं हो पाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांवों के विकास और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन होता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर पंचायत कार्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है।

इस संबंध में पंचायत सचिव का पक्ष भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने निवास स्थान पर होने की जानकारी दी। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।



योगदान हो। कार्यक्रम समन्वयक टेकराम सेन ने अपने साहित्यिक अंदाज में छात्राध्यापकों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि धुएं से

कि न हम स्वयं तंबाकू का सेवन करें, बल्कि समाज व परिवार को भी इससे बचाएं। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापक के सिंग, सुनमा द्विवेदी, राजेश चंद्राकर, व्याख्याता संतोष साहू, किरण कन्नौजे, सुमन दीवान, दुर्गा सिन्हा, तिलोत्तमा प्रधान, लक्ष्मी सिन्हा, ईश्वर चंद्राकर, झरना साहू ने भी छात्राध्यापकों को संबोधित किया। छात्राध्यापक मीना ठाकुर ने नेतृत्व में सभी छात्राध्यापकों ने धूम्रपान से परिवार व समाज को बचाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर हीमन, अजय, उदित सहित छात्राध्यापक शुभम पोते, धर्मेन्द्र जगत, घनश्याम पटेल, अनिकेत कंवर, टोमन भंजारी, मीना ठाकुर, माधुरी मंडावी, भावना दीवान, भारती कालसा, प्रीति सिंह सहित द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक व्याख्याता टेकराम सेन ने किया। उक्त जानकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से व्याख्याता संतोष साहू ने दी है।

स्वास्थ्य सेवाओं में मुंगेली बना प्रदेश का मॉडल, स्वास्थ्यांक ग्रेडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

स्वास्थ्य विभाग की टीम भावना से किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप मुंगेली जिला प्रदेश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य जिलों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और 50 प्रमुख स्वास्थ्य सूचकों पर उपलब्धि हासिल करने के कारण मुंगेली जिला वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिलों की

का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संवेदनशील प्रशासन, सतत मॉनिटरिंग और टीमवर्क के माध्यम से जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। मुंगेली ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में 98 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई, जबकि संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 99.98 रहा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु दल द्वारा चिन्हित 99.9 प्रतिशत बीमार बच्चों का उपचार भी सुनिश्चित किया गया।

ईपीएफ प्रकरणों में श्रमिकों की बैठक

लंबित मामलों पर चर्चा

रायपुर। नगर निगम गार्डन में रविवार को लोक निर्माण विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग रायपुर के दैनिक श्रमिकों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में की गई। बैठक में प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारी, विभिन्न संभागों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में प्रभावित श्रमिक शामिल हुए। बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्ष 2021 से 2024 की अवधि के संबंध में जारी नोटिस, विभागीय स्थिति, पात्र श्रमिकों के ईपीएफ अंशदान तथा लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में संबंधित विभागीय अधिकारियों, प्रमुख अभियंता, सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ईपीएफ अधिकारियों से पुनः समन्वय स्थापित कर प्रकरण के त्वरित निराकरण के लिए प्रभावी पहल की जाएगी। संगठन ने सभी श्रमिकों से एकजुट रहने तथा आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, ताकि लंबित ईपीएफ राशि एवं अन्य वैधानिक लाभों की प्राप्ति की प्रक्रिया को गति मिल सके। बैठक में संघ के प्रांताध्यक्ष राकेश साहू ने कहा कि संगठन श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। ईपीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता है।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों में किया जाएगा खाद्यान्न वितरण शीघ्र

महासमुंद। माह नवंबर 2025 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के संबंध में खाद्य निरीक्षक पिथौरा ने बताया कि पिथौरा विकासखंड की सहकारी समितियों द्वारा संचालित 19 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल के कारण निधारित अवधि में खाद्यान्न वितरण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि हितवाहियों को खाद्यान्न प्राप्त सुनिश्चित करने के लिए समन्वय पर आवश्यक पात्राचार किया गया। माह नवंबर 2025 के वितरण के लिए माह दिसंबर 2025 में विकल्प प्रदान किए जाने के लिए 13 दिसंबर 2025 को कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) को पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अलावा जिला स्तर से भी संचालनालय को 02 दिसंबर 2025 एवं 15 दिसंबर 2025 को पत्र भेजकर माह नवंबर 2025 के लंबित वितरण के लिए विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जैसे ही संचालनालय स्तर से माह नवंबर 2025 के वितरण के लिए आवश्यक विकल्प प्राप्त होगा, वैसे ही हितवाहियों को माह नवंबर 2025 का खाद्यान्न वितरण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में हितवाहियों को जानकारी दी जाएगी।

कांग्रेस ने कहा- स्काईवॉक तोड़कर बनाएं प्लाईओवर



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्काई वॉक शहर की जनता की गले की हड्डी बन चुका है। रोज इसके पैनल गिर रहे हैं। राहगीरों की जान खतरों में पड़ी रहती है। भाजपा सरकार अपनी जिद छोड़े और शहर की जनता से माफ़ी मांगकर स्काई वॉक तोड़कर वहां प्लाईओवर बनाए, जिसकी आज जरूरत है। उन्होंने कहा, स्काईवॉक

भाजपा के भ्रष्टाचार की स्मारक के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा है। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा बिना किसी आवश्यकता के रायपुर शहर में एक स्काईवॉक बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया।

रव. श्री दुकलु राम साहू जी

आज दशगात्र

अत्यंत दुःख के साथ सुचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री दुकालू राम साहू जी** (सेवानिवृत्त शिक्षक) का स्वर्गवास दि. 27.05.2026 दिन बुधवार को हो गया है। जिसके कार्यक्रम में आप सहपरिवार उपस्थित होकर मृतात्मा को शान्ति प्रदान करें-

दशगात्र दिनांक - 02/06/2026

दिन मंगलवार स्थान- निज निवास ग्राम लाफिन खुर्द जिला महासमुंद टीप:- तालाब कार्यकर्म 12 बजे

कार्यक्रम-

श्रीकामकुल परिवार-

नीलमणि, राहुल, मोहन, रिछी, भेखलाल, भुनेश्वर, वेदप्रकाश, बबलू, मोनू, यशराज, शिगर, वंश, एवं समस्त साहू परिवार

भित्त-

भारतभूषण-भारती (पुत्र-बह)
भीम - झमन (पुत्र-बह)
मो. 8827681912, 8878697143

विनंति :- आदर के टेटर्स एवं भीम किशन स्टोर्स, लाफिनखुर्द

नोट : जिन स्नेहीजनों को सोकग्रन व मिलत रहे, कृपया इसे ही स्वीकार करें...

HEALTH TOWN

DR. ABHIMANYU'S
AYURVEDA MULTISPECIALITY HOSPITAL
PAIN | PANCHANGA | PILES | PEGAS | GYNAC | SKIN

> रात गोट > पुल्के के दर्द > पीठ व कमर दर्द > स्पाइडलाइटल > शिगागेट के दर्द
> स्पाइडलाइट > ओफो एक्को > फ्लेक्स लोअर > शरीर में जकड़न

कैंसर, रक्त, यकृतियों व सभी प्रकार के दर्द का इलाज

9 सिटी सेंटर - कृष्णा टीकीज के सामने, रमला कॉलोनी रायपुर (छ.ग.) ☎ 9826446666
9 रोक्टर -7 कमल विहार, रायपुर (छ.ग.) ☎ 95224-66664, 62622-22003

Piles Care Clinic

ISO 9001:2015 Certified Clinic | Unit of Dr. Abhimanyu's Pain Relief Center

किता चौकाड़ के नावरीर (वाइसर), फिटुला (गलांटर) फिगार, फिलिफिडा राइसराज

सेजूर मशीन / क्षार सूत्र द्वारा आयरने की सुविधा

लेडिस डॉक्टर उपलब्ध

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130

